



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 676) पटना, मंगलवार, 16 जून 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं  
28 मई 2015

सं0 7/स्था0-1-4-05/2011सा0प्र0-7803—भारत-संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**— (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 2(ख) का प्रतिस्थापन।**— उक्त नियमावली का नियम 2(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-  
“(ख) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पद पर भर्ती उच्च न्यायालय द्वारा नियम 24 के अधीन संपुष्ट या नियम 26 के अधीन नियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट ‘च’ में यथाअंतर्विष्ट उपयुक्तता प्राचल (पैरामीटर) के अधीन रहते हुए वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर की जायेगी।”
3. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 में निम्नलिखित एक नया परिशिष्ट ‘च’ जोड़ा जायेगा:-

“परिशिष्ट-च

**असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) संवर्ग में अधिकारियों की प्रोन्नति हेतु प्राचल (पैरामीटर)**

- (1) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) संवर्ग में पदाधिकारी 5 वर्षों से अन्यून सेवा अवश्य कर ली हो।
- (2) पदाधिकारी को विगत 5 वर्षों में उनके द्वारा पारित न्याय निर्णयों के मूल्यांकन के आधार पर कम-से-कम 40 अंक प्राप्त की हो, इस प्रयोजनार्थ सामान्यतः उनके द्वारा तीन फौजदारी एवं दो दीवानी अधिकारिता के मुकदमों में पारित न्यायादेशों का मूल्यांकन किया जायेगा।
- (3) 20 त्रैमासिकों के दौरान अथवा उसी अनुपात में विगत 5 वर्षों के दौरान पदाधिकारी को कार्य संपादन आंकने में Poor/Cl/Fair/Average की 10 या अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त न हों, जिसमें असफल होने पर, वह प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ निरर्हित होगा।

स्वपुनर्मूल्यांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

- (4) पदाधिकारी के विगत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि के आधार पर उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा।
- (5) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, यथा और जब अपेक्षित हो, परिशिष्ट 'च' में अंतर्विष्ट प्राचल (पैरामीटर) को उपांतरित कर सकेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो० जफर रकीब,  
सरकार के उप-सचिव।

28 मई 2015

सं०7/स्था०-1-4-05/2011सा०प्र० 7804/अधिसूचना संख्या-7803 दिनांक 28.05.2015 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो० जफर रकीब,  
सरकार के उप-सचिव।

*The 28<sup>th</sup> May 2015*

No. 7/Ashta-1-4-05/2011GAD-7803—In exercise of the powers conferred by Article 234 of constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules-1955 in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission :-

1. **Short title, extent and commencement.** —(1) This Rules may be called Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Amendment Rules. 2015  
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.  
(3) It shall come into force at once.
2. **Substitution of Rule 2 (b) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.**— Rule 2(b) of the said Rules shall be substituted by the following :-  
“(b)- Recruitment to the posts of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the High Court, by promotion of Civil Judge (Junior Division) confirmed under Rule 24 or appointed under Rule 26, on the basis of seniority-cum-merit subject to the suitability parameters as contained in Appendix 'E'.”
3. The following a new Appendix 'E' shall be added to the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-

#### **"APPENDIX- E**

#### **Parameters for promotion of officers form Civil Judge (Junior Division) to the cadre of Civil Judge (Senior Division)**

- (1) The officer must have served for not less than 5 years in the cadre of Civil Judge (Junior Division).
- (2) An officer must obtain minimum of 40% marks on the basis of evaluation of his judgments delivered in the last 5 years. Ordinarily Judgments passed in 3 criminal and 2 civil jurisdiction cases shall be evaluated for this purpose.
- (3) In work performance appraisal, the officer must not have scored 10 or more entries of Poor/CI/Fair/Average during the 20 quarters or in that proportion during last 5 years, failing which he shall stand disqualified for the purpose of promotion.

Explanation submitted with the self reappraisal, if any, may be considered in respect of relevant entries.

- (4) Suitability shall be assessed on the basis of entries in the Annual Confidential Report of the last 5 years.

- (5) The State Government, after the consultation with the High Court, as and when required, may modify the parameters contained in Appendix 'E'."

By order of the Governor of Bihar,  
MD. ZAFAR RAKIB,  
*Deputy Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 676-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>